

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

(एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा)

**दांडिक अपील क्रमांक 206 वर्ष 2004**

वीरचंद जैन

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

**निर्णय**

दिनांक 09-04-2012

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश





**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

(एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा)

**दांडिक अपील क्रमांक 206 वर्ष 2004**

**अपीलार्थी**  
(जेल में)

वीरचंद जैन, पिता टिकाराम जैन, उम्र लगभग 48 वर्ष,  
जगदीश टाकिज के पास, दमोह, मध्य प्रदेश। वर्तमान में  
जूनियर इंजिनियर के पद पर कार्यरत, छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड,

कसडोल, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

बनाम

**प्रत्यर्थी**

छत्तीसगढ़ राज्य

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

(एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा)

**उपस्थित:** डॉ. एन. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आदित्य खरे, अपीलार्थी के अधिवक्ता के साथ उपस्थित थे।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता राज्य/प्रत्यर्थी हेतु।

दंड प्रक्रिया संहिता की धरा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपीलआदेश

(09 अप्रैल, 2012)

यह अपील रायपुर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा विशेष प्रकरण संख्या 11/2002 में दिनांक 20-2-2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलकर्ता वीरचंद जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1988' कहा गया है) की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) के साथ धारा 13(2) के तहत सिद्धदोष पाया गया है और निम्नलिखित तरीके से सजा सुनाई गई है तथा सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:

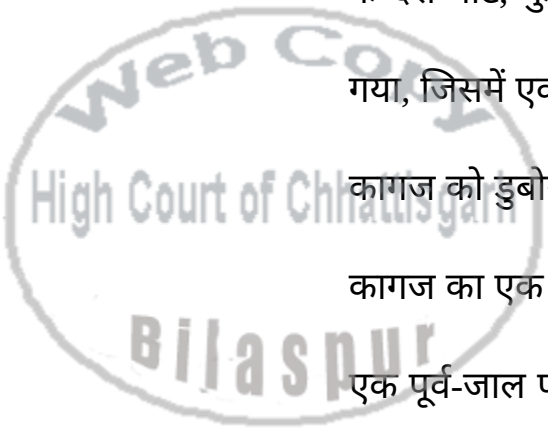
दोषसिद्धि	दंडादेश
धारा 7 की अधिनियम, 1988 के अंतर्गत	दो साल के सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने के व्यतिक्रम पर 6 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 13(1)(घ) के साथ धारा 13(2) की अधिनियम, 1988 के तहत	पांच साल के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने के व्यतिक्रम पर 6 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है:

2. अपीलकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, खरोरा में एक कनिष्ठ अभियंता थे। 15-1-2002 को, परिवादी रामावतार देवांगन (अ.सा.-4), निवासी ग्राम केसला, चौकी खरोरा, जिला रायपुर ने लोकायुक्त, रायपुर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित



परिवाद (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता ने बिना सूचना दिए उनके ट्यूबवेल की बिजली काट दी थी और उसे दोबारा जोड़ने के लिए 2,000 रुपये की रिश्त मांग रहा था। परिवादी (प्रदर्श पी/1) को आवश्यक कार्रवाई के लिए निरीक्षक एन.एस. चौबे (अ.सा.-6) को भेज दिया गया। परिवाद (प्रदर्श पी/1) प्राप्त होने पर, एन.एस. चौबे (अ.सा.-6) ने पंच गवाहों एस.एस. पांडे (अ.सा.-1) और एम.एस. मांडवी को बुलाया। दोनों पंच गवाहों को परिवाद (प्रदर्श पी/1) उनके अवलोकन के लिए दी गई। उन्होंने परिवादी रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) से परिवाद के बारे में पूछताछ की। इसके बाद, परिवादी ने 500 रुपये के दो नोट और 100 रुपये के दस नोट, कुल 2,000 रुपये प्रस्तुत किए। एक पूर्व-जाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। घोल में सादे कागज को डुबोने पर उसका रंग नहीं बदला। इसके बाद, फिनोलफथेलिन पाउडर युक्त कागज का एक और टुकड़ा को उसमें डूबा के घोला गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। एक पूर्व-जाल पंचनामा (प्रदर्श पी/5) तैयार किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए करेंसी नोटों की संख्या पूर्व-जाल पंचनामा (प्रदर्श पी/5) में दर्ज की गई। करेंसी नोट प्रस्तुत करने के बाद, उन पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया गया और नोटों को परिवादी की कमीज की ऊपरी बाईं जेब में रख दिया गया। परिवादी को निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया कि जाल कैसे बिछाया जाएगा और उसे इस प्रक्रिया में क्या भूमिका निभानी है। जाल बिछाने वाली टीम खरोरा के लिए रवाना हुई। अपीलकर्ता अपने घर पर मौजूद नहीं था। उस समय अपीलकर्ता बालाजी राइस मिल में बैठा था। परिवादी ने उससे फोन पर संपर्क किया। अपीलकर्ता ने उसे बालाजी राइस मिल में बुलाया। इसके बाद, जाल बिछाने वाली टीम बालाजी राइस मिल के लिए रवाना हुई। अपीलकर्ता राइस मिल के कार्यालय में प्रकाश अग्रवाल (व.सा.-1) के साथ बैठा था।





परिवादी ने अपीलकर्ता को 2,000 रुपये के नोट दिए। इसके बाद, परिवादी ने जाल बिछाने वाली टीम को संकेत भेजा। जाल बिछाने वाली टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अपीलकर्ता को पकड़ लिया। टीम ने अपीलकर्ता की कमीज की जेब से 2,000 रुपये के नोट जब्त किए। जब्त किए गए नोटों के नंबरों की तुलना जाल बिछाने से पहले के पंचनामा (प्रदर्श पी/5) में उल्लिखित नंबरों से की गई, जो समान पाए गए। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया और अपीलकर्ता की उंगलियों को घोल में डुबोया गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। इसके बाद, घोल को एक बोतल में भरकर सील कर दिया गया। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया जिसमें अपीलकर्ता की कमीज की जेब को डुबोया गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। घोल को दूसरी बोतल में भरकर सील कर दिया गया। एक और सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया और जब्त किए गए करेंसी नोटों को घोल में डुबोया गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। घोल को एक दूसरी बोतल में भरकर सील कर दिया गया। इसके बाद, ट्रेप-पंचनामा (प्रदर्श पी/7) तैयार किया गया और करेंसी नोटों को प्रदर्श पी/9 के तहत जब्त किया गया। स्पॉट-मैप (प्रदर्श पी/12) तैयार किया गया। नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/25) दर्ज की गई। जब्त की गई वस्तुओं को जांच के लिए रायपुर स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। वहां से रिपोर्ट (प्रदर्श पी/29) प्राप्त हुई। रिपोर्ट (प्रदर्श पी/29) में फिनोलफथेलिन परीक्षण सकारात्मक पाया गया।

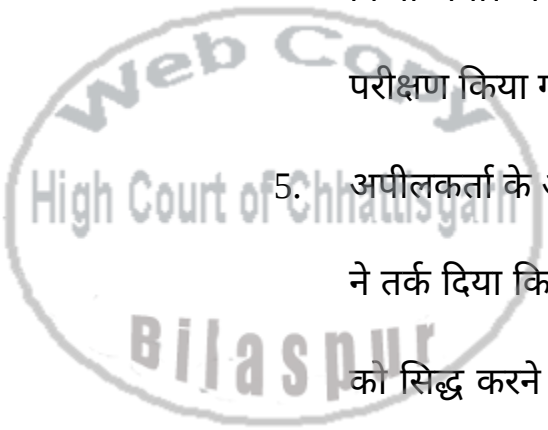
अन्वेषण पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त की गई और रायपुर के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) के साथ धारा 13(2) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप विचरित किए गये।





3. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के बाद, माननीय विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष पाया और सजा सुनाई।
4. अपीलकर्ता/आरोपी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने एस.एस. पांडे (प्रत्यक्षदर्शी-1), रामानंद सोनी (प्रत्यक्षदर्शी-2), अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता पी.एन. सिंह (प्रत्यक्षदर्शी-3), परिवादी रामावतार देवांगन (प्रत्यक्षदर्शी-4), कांस्टेबल अमलदास लकड़ा (प्रत्यक्षदर्शी-5), निरीक्षक एन.एस. चौबे (प्रत्यक्षदर्शी-6), निरीक्षक विश्वास चंद्रकार (प्रत्यक्षदर्शी-7), पुलिस उप अधीक्षक आर.के. शर्मा (प्रत्यक्षदर्शी-8) और अधीक्षण अभियंता पी.एस. कुमार (प्रत्यक्षदर्शी-9) के परीक्षण किया गया। बचाव पक्ष में, अपीलकर्ता ने प्रकाश चंद्र अग्रवाल (प्रत्यक्षदर्शी-1) का परीक्षण किया गया।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री आदित्य खरे के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय और ठोस साक्ष्यों से अवैध रिश्वत की मांग को सिद्ध करने में विफल रहा है। एस.एस. पांडे (अ.सा.-1) ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उन्होंने अपीलकर्ता को परिवादी से अपनी ओर से पैसे मांगते हुए नहीं सुना था। एस.एस. पांडे (अ.सा.-1), पी.एन. सिंह (अ.सा.-3) और पी.एस. कुमार (अ.सा.-9) के साक्ष्यों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली की आपूर्ति इसलिए काट दी गई थी क्योंकि अपीलकर्ता मोटर पंप का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था और पानी बेच रहा था। परिवादी ने बिजली कनेक्शन बहाल करने और बकाया राशि के लिए अपीलकर्ता को 2,000 रुपये का भुगतान किया था। अवैध रिश्वत की मांग, जो कि अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) के साथ धारा 13(2) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अनिवार्य शर्त है, सिद्ध नहीं हुई है। अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता





को दोषी ठहराने से पहले अभियोजन पक्ष के लिए अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) को धारा 13(2) के सभी तत्वों को साथ मिलाकर सभी शर्तों को पूरा करना और स्थापित करना आवश्यक है। उनका कहना है कि आक्षेपित निर्णय कानून की दृष्टि से स्थिर रखने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि अनुमान लगाने के बाद भी, अपीलकर्ता ने यह स्थापित कर दिया है कि उसने अवैध रिश्वत के रूप में धन स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने एस.एस. पांडे (प्रत्यक्षदर्शी-1), रामानंद सोनी (प्रत्यक्षदर्शी-2), पी.एन. सिंह (प्रत्यक्षदर्शी-3) और पी.एस. कुमार (प्रत्यक्षदर्शी-9) के साक्ष्यों को देखते हुए तर्क दिया कि उनके साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि परिवादी ने अपीलकर्ता को बिजली कनेक्शन बहाल करने और बकाया राशि के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया था। इसलिए, आक्षेपित निर्णय स्थिर रखने योग्य नहीं है और अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाने योग्य है।

6. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए उपरोक्त तर्कों का खंडन किया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। रिश्वत की राशि अपीलकर्ता से बरामद की गई थी। जब अपीलकर्ता की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इसलिए, अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध एक अनुमान बनता है और उसके विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
7. पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने विशेष प्रकरण संख्या 11/2002 के अभिलेख का अवलोकन किया है।



8. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के बाद यह माना कि अपीलकर्ता ने परिवादी से 2,000 रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी और उसने परिवादी से अवैध रिश्वत स्वीकार की थी।
9. रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) ने गवाही दी कि अपीलकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के खरोरा स्थित कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात था। उसने अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाया था और उसका बिजली कनेक्शन लिया था। 13-1-2002 को अपीलकर्ता ने उक्त ट्यूबवेल की बिजली काट दी थी। इस संबंध में उसकी मुलाकात अपीलकर्ता से हुई थी। अपीलकर्ता ने बिजली कनेक्शन बहाल करने के बदले उससे 3,000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे। उसने अपीलकर्ता से कहा कि वह उसे पहले ही 4,000 से 5,000 रुपये दे चुका है, तो उसे और कितनी रकम देनी होगी। उसने आगे गवाही दी कि उसने रायपुर स्थित लोकायुक्त कार्यालय में लिखित परिवाद (प्रदर्श पी/1) प्रस्तुत की थी और वहां से एक टेप रिकॉर्डर प्राप्त किया था। इसके बाद वह खरोरा गया और एक पान की दुकान पर अपीलकर्ता से मिला और अपने ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन बहाल करने के लिए उससे बात की। उस समय अपीलकर्ता ने उससे रिश्वत के तौर पर 2,000 रुपये की मांग की थी। उसने अपने और अपीलकर्ता के बीच हुई बातचीत को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था।
10. एन.एस. चौबे (अ.सा.-6) ने गवाही दी कि उन्हें अपीलकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए एक लिखित परिवाद मिली थी। उन्होंने परिवादी को एक टेप रिकॉर्डर दिया था और इस संबंध में एक पंचनामा भी तैयार किया था (प्रदर्श पृष्ठ-24)। परिवादी ने उन्हें रिकॉर्ड किया हुआ टेप रिकॉर्डर लौटा दिया था, जिसे उन्होंने गवाहों की उपस्थिति में सुना था और उसकी प्रतिलिपि भी तैयार की थी (प्रदर्श पृष्ठ-2)। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने परिवादी से परिवाद (प्रदर्श पृष्ठ-1) के बारे में पूछताछ की।





उन्होंने दो पंच गवाहों एस.एस. पांडे (अ.सा.-1) और एम.एस. मांडवी को बुलाया और उन्हें परिवादी से मिलवाया। उन्होंने उन्हें परिवाद (प्रदर्श पृष्ठ-1) परिशीलन के लिए दी। पंच गवाहों ने परिवाद (प्रदर्श पी/1) का अध्ययन किया और परिवादी से परिवाद के बारे में पूछताछ की। एक पूर्व-जाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। एक सादे कागज को घोल में डुबोया गया, लेकिन घोल का रंग नहीं बदला। परिवादी से 2,000 रुपये के नोट पेश करने को कहा गया। परिवादी ने 500 रुपये के दो नोट और 100 रुपये के दस नोट, कुल मिलाकर 2,000 रुपये प्रस्तुत किए, जिन पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगा हुआ था। ये नोट परिवादी की कमीज की बाईं ऊपरी जेब में रखे गए थे। परिवादी को बताया गया और मार्गदर्शन दिया गया कि जाल कैसे बिछाया जाएगा और इस प्रक्रिया में परिवादी को क्या भूमिका निभानी होगी। एस.एस. पांडे (प्रथम साक्षी) और अमलदास लकड़ा (पांचवां साक्षी) ने भी इसी तरह गवाही दी।

11. एस.एस. पांडे (अ.सा.-1), रामावतार देवांगन (अ.सा.-4), अमलदास लकड़ा (अ.सा.-5), एन.एस. चौबे (अ.सा.-6) और आर.के. शर्मा (अ.सा.-8) ने गवाही दी कि वे खरोरा के लिए रवाना हुए थे। परिवादी रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) और कांस्टेबल अमलदास लकड़ा (अ.सा.-5) अपीलकर्ता का पता लगाने गए थे। कुछ समय बाद, वे वापस आए और बताया कि अपीलकर्ता चावल मिल में मौजूद है। परिवादी रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) ने गवाही दी कि अपीलकर्ता ने उन्हें चावल मिल में पैसे के साथ बुलाया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि वे चावल मिल की ओर रवाना हुए, जहां अपीलकर्ता मौजूद था। केवल परिवादी और अमलदास लकड़ा (अ.सा.-5) चावल मिल के अंदर गए और जाल बिछाने वाली टीम के अन्य सदस्य मिल के बाहर खड़े रहे।



12. रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) ने गवाही दी कि अपीलकर्ता चावल मिल के मालिक प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-1) के साथ चाय पी रहा था। उन्हें भी चाय परोसी गई और उन्होंने चाय पी ली। इसके बाद, उन्होंने अपीलकर्ता को 2,000 रुपये के नोट दिए, जिन्हें अपीलकर्ता ने अपनी कमीज की जेब में रख लिया। फिर उन्होंने अपीलकर्ता से कहा कि उनके ट्यूबवेल की बिजली अब बहाल हो गई होगी। अपीलकर्ता ने उन्हें बताया कि बिजली बहाल हो गई होगी। उन्होंने आगे गवाही दी कि वे बाहर आए और जाल बिछाने वाली टीम को संकेत भेजा।
13. रामावतार देवांगन (अ.सा.-4), अमलदास लकड़ा (अ.सा.-5), एन.एस. चौबे (अ.सा.-6) और आर.के. शर्मा (अ.सा.-8) ने गवाही दी कि रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) से संकेत मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और अपीलकर्ता को पकड़ लिया। पूछे जाने पर अपीलकर्ता ने रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) से धन प्राप्त करने की बात स्वीकार की।
14. एन.एस. चौबे (अ.सा.-6) और आर.के. शर्मा (अ.सा.-8) ने गवाही दी कि सोडियम कार्बोनेट का एक घोल तैयार किया गया जिसमें अपीलकर्ता की उंगलियों को डुबोया गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। घोल को एक अलग और साफ बोतल में रखा गया और सील कर दिया गया। पंच गवाह एम.एस. मांडवी ने अपीलकर्ता की कमीज की जेब से 2,000 रुपये के नोट बरामद किए। जब्त किए गए नोटों की संख्या का मिलान प्री-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी/5) में उल्लिखित संख्याओं से किया गया, जो समान पाई गईं। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया और जब्त किए गए नोटों को उसमें डुबोया गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। घोल को एक दूसरी बोतल में रखा गया और सील कर दिया गया। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया जिसमें अपीलकर्ता की कमीज की जेब को डुबोया गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। उस घोल को एक दूसरी बोतल में रखकर सील कर दिया गया।





15. एस.एस. पांडे (प्रत्यक्षदर्शी-1), रामावतार देवांगन (प्रत्यक्षदर्शी-4), अमलदास लकड़ा (प्रत्यक्षदर्शी-5), एन.एस. चौबे (प्रत्यक्षदर्शी-6) और आर.के. शर्मा (प्रत्यक्षदर्शी-8) के साक्ष्यों की जांच करने के बाद, यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता से 2,000 रुपये बरामद किए गए थे और जब्त किए गए करेंसी नोटों की संख्या का प्री-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी/5) में उल्लिखित संख्याओं से मिलान करने पर, वे समान पाए गए।
16. अब, मैं यह जांच करूंगा कि क्या करेंसी नोटों की मात्र बरामदगी, अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) को धारा 13(2) के अधीन अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है?
17. अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध गठित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि धन की मांग की गई थी और आरोपी ने उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया था। इसी प्रकार, अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के अनुसार, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी कार्य के बदले धन की मांग करना और उसे स्वीकार करना, अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य शर्त है।
18. **बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 4 एससीसी 450** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

“24. एम.के. हर्षन बनाम केरल राज्य, (1996) 11 एससीसी 720 में, इस न्यायालय ने कुछ समान परिस्थितियों में, जहां दूषित धन आरोपी के दराज में रखा गया था, जिसने इससे इनकार किया और कहा कि यह उसकी जानकारी के बिना दराज में रखा गया था, निम्नानुसार निर्णय दिया: (एससीसी पृष्ठ 723-24, पैरा 8)

"8. ... इसी संदर्भ में न्यायालयों ने आगाह किया है कि विवेक के नियम के रूप में, कुछ पुष्टि आवश्यक है। रिश्वतखोरी के इस प्रकार



के सभी मामलों में, दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला, मांग होनी चाहिए और दूसरा, स्वीकृति होनी चाहिए, इस अर्थ में कि आरोपी ने अवैध रिश्वत प्राप्त की है। केवल मांग ही अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।" इसलिए, दूसरा पहलू, यानी स्वीकृति, बहुत महत्वपूर्ण है और जब आरोपी ने यह अभिग्रह किया है कि करेंसी नोट उसकी जानकारी के बिना दराज में रखे गए थे, तो यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए कि आरोपी की मौन सहमति से ही अवैध रिश्वत के रूप में पैसा दराज में रखा गया था। दुर्भाग्य से, वर्तमान प्रकरण में इस पहलू पर हमारे पास अ.सा.1 के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है। चूंकि अ.सा.1 के साक्ष्य में खामियां हैं, इसलिए हमने इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। ऐसा कोई अन्य गवाह या कोई अन्य परिस्थिति नहीं है जो अ.सा.1 के इस साक्ष्य का समर्थन करती हो कि आरोपी के निर्देशानुसार रिश्वत के रूप में यह दूषित धन दराज में रखा गया था। जब तक हम इस पहलू से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक यह मानना मुश्किल है कि आरोपी ने अवैध रिश्वत को मौन रूप से स्वीकार किया या अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के अर्थ में उसे प्राप्त किया, विशेष रूप से तब जब आरोपी का बयान संभावित प्रतीत होता है।"

25. अपीलकर्ता की ओर से इस न्यायालय के *सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779* के निर्णय पर अवलंब लिया गया था, जहां मामले के तथ्यों में न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि मांग और स्वीकृति के लिए ठोस सबूतों के अभाव में आरोपी





से केवल धन की बरामदगी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने माना कि रिश्वत समझकर धन की स्वैच्छिक स्वीकृति नहीं थी और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का लाभ उठाते हुए, न्यायालय ने निर्णय के पैरा 18 और 20 में निम्नानुसार कहा: (एससीसी पृष्ठ 784 और 785-86)

“18. *सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979)*  
4 एससीसी 725 के मामले में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, पैरा 2 पर) केवल दूषित धन की बरामदगी, उसे भुगतान किए जाने की परिस्थितियों से अलग करके, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में ठोस साक्ष्य विश्वसनीय न हो। रिश्वत के भुगतान को साबित करने वाले या यह दर्शाने वाले किसी भी साक्ष्य के अभाव में कि आरोपी ने स्वेच्छा से रिश्वत समझकर धन स्वीकार किया था, केवल बरामदगी ही आरोपी के विरुद्ध अभियोजन के आरोप को सिद्ध नहीं कर सकती।

20. *एम. नरसिंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2001) 1 एससीसी 691* में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तर्क पर विचार करते हुए कि लोक सेवक को कुछ मुद्रा नोट सौंपना ही रिश्वत की स्वीकृति नहीं है और अभियोजन पक्ष का यह भी कर्तव्य है कि वह साबित करे कि भुगतान की गई राशि रिश्वत थी, टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 700, पैरा 24)

‘24. ... हमें लगता है कि वर्तमान प्रकरण पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए हाल के





एक निर्णय में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई है। (देखें *मधुकर भास्करराव जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2000) 8 एससीसी 571*)  
उक्त निर्णय में हमारे द्वारा दिया गया निम्नलिखित कथन विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्क का उत्तर होगा: (*मधुकर प्रकरण, एससीसी पृष्ठ 577, पैरा 12*)

“12. अनुमान लगाने के लिए तथ्यों पर स्थापित की जाने वाली शर्त यह है कि रिश्वत का भुगतान या स्वीकृति हुई थी। एक बार जब यह शर्त स्थापित हो जाती है, तो निष्कर्ष यह निकाला जाना चाहिए कि उक्त रिश्वत किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए 'हेतुक या पुरस्कार' के रूप में स्वीकार की गई थी। इसलिए 'रिश्वत' शब्द को पुरस्कार के अर्थ में विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुरस्कार उस अनुमान का परिणाम है जो न्यायालय को इस तथ्यात्मक आधार पर लगाना होता है कि रिश्वत का भुगतान हुआ था। यह दो अभिव्यक्तियों के एक साथ आने से और भी पुष्ट होगा जैसे 'रिश्वत या कोई मूल्यवान वस्तु'। यदि किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति इस अनुमान को लगाने में सहायक हो सकती है कि यदि इसे किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए हेतुक या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो 'प्रतिशोध' शब्द को उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें लोक सेवक को संतुष्टि प्रदान करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान शामिल हो।” ’ ’





वास्तव में, उपरोक्त सिद्धांत किसी भी तरह से व्युत्पन्न नहीं है, बल्कि *सूरज मल* मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की पुनरावृत्ति है, जहां न्यायालय ने माना था कि रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए कि आरोपी ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किया था, किसी भी साक्ष्य के अभाव में केवल वसूली से ही आरोपी के खिलाफ अभियोजन का आरोप साबित नहीं हो सकता। *सीता राम बनाम राजस्थान राज्य*, (1975) 2 एससीसी 227 में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जहां इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

19. **टी. सुब्रमणियन बनाम तमिलनाडु राज्य (2006) 1 एससीसी 401** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) को धारा 5(2) के साथ अंतर्गत पर, अवैध रिश्वत के रूप में धन की मांग और स्वीकृति के प्रमाण के अभाव में, केवल अभियुक्त द्वारा धन की प्राप्ति का प्रमाण अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि अभियुक्त साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त और संभावित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है कि धन को उसने अवैध रिश्वत के अलावा किसी अन्य रूप में स्वीकार किया था, तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार होगा।
20. **सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 4 एससीसी 725** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि रिश्वत के भुगतान को सिद्ध करने या यह दिखाने के लिए कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किया था, किसी भी साक्ष्य के अभाव में, केवल बरामदगी से अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं हो सकता।
21. केरल उच्च न्यायालय, सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन (2009) 3 एससीसी 779 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

"18. *सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)*, (1979) 4 एससीसी



725 में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, पैरा 2 पर) केवल दूषित धन की बरामदगी, उसे भुगतान करने की परिस्थितियों से अलग करके, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में ठोस साक्ष्य विश्वसनीय न हो। रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए कि आरोपी ने स्वेच्छा से रिश्वत समझकर धन स्वीकार किया, किसी भी साक्ष्य के अभाव में, केवल बरामदगी ही आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं कर सकती।

22. यह भी सर्वविदित है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत जिस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अनुमान लगाया जाता है, उस पर डाला गया सबूत का बोझ, अभियोजन पक्ष पर युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित करने के बोझ के समान नहीं है।

"4. .... यह संस्थापित है कि जहां किसी मुद्दे का भार आरोपी पर होता है, वहां उसे अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करके उस भार को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह, निश्चित रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के अपराध को साबित करने के भार को पूरा करने के निर्धारण में निर्धारित कसौटी है; लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत उस पर लगाए गए भार को पूरा करने की मांग करने वाले आरोपी व्यक्ति पर यही कसौटी लागू नहीं की जा सकती। यदि आरोपी व्यक्ति अपने मामले के पक्ष में प्रबल संभावना साबित करने में सफल होता है तो यह पर्याप्त है। आरोपी व्यक्ति के लिए अपने मामले को युक्तियुक्त





संदेह से परे साबित करना आवश्यक नहीं है, अन्यथा उसे दोषी ठहराया जाएगा। आरोपी व्यक्ति पर साक्ष्य का भार प्रबल संभावना से अपने मामले को साबित करना है। जैसे ही वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, दायित्व अभियोजन पक्ष पर आ जाता है, जिसे अभी भी अपना मूल दायित्व निभाना होता है जो कभी नहीं बदलता, अर्थात् पूरे मामले में आरोपी के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना। (जोर दिया गया) (देखें *वी.डी. झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, एआईआर 1966 एससी 1762 एआईआर पृष्ठ 1764, पैराग्राफ 4)

22. **केरल राज्य और अन्य बनाम सी.पी. राव, (2011) 6 एससीसी 450** में, माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"7. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विशेष रूप से अ.सा.1 की गैर-परीक्षा को उच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के *पनालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (1979) 4 एससीसी 526 के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना था कि जब आरोपी द्वारा रिश्त की मांग के संबंध में परिवादी की गवाही की पुष्टि नहीं होती है, तो यह स्वीकार करना होगा कि परिवादी के बयान की पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए, परिवादी के साक्ष्य पर अवलंब नहीं लिया जा सकता। उपरोक्त परिस्थितियों में, पनालाल दामोदर राठी मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह है और प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। (एससीसी



पैरा 11 देखें।)"

10. सी. एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 में, इस न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए, सूरज मल बनाम स्टेट (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725 में अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए यह माना कि जब मामले में ठोस साक्ष्य विश्वसनीय न हो, तो केवल दूषित धन की बरामदगी, उसे दिए जाने की परिस्थितियों से अलग, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल बरामदगी से ही आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप सिद्ध नहीं हो सकते। रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए कि आरोपी ने स्वेच्छा से रिश्वत समझकर धन स्वीकार किया, किसी भी साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। (देखें एससीसी पैरा 18।)

11. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इसी न्यायालय के एक बाद के निर्णय, ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, (2009) 6 एससीसी 587 में, इस न्यायालय ने रिश्वतखोरी के मामले में परिवादी की उपस्थिति की आवश्यकता के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गईं। प्रासंगिक टिप्पणियाँ अनुच्छेद 18-19 में की गई हैं, जो नीचे उद्धृत हैं: (एससीसी पृष्ठ 592)

"18. .... उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि विशेष न्यायाधीश ने परिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वे प्रयास विफल रहे क्योंकि वह भारत में उपलब्ध नहीं था, इसलिए परिवादी की जांच न करने का औचित्य था।





19. हमें उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना कठिन लगता है। जांच अधिकारी द्वारा परिवादी की जांच न करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण, अधिनस्त न्यायालयों के लिए परिवादी को साक्ष्य में प्रस्तुत न करने का अपना कारण खोजना युक्तियुक्त नहीं था। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि मांग को साबित करने के लिए सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया था।"

12. ऊपर उद्धृत वे टिप्पणियाँ वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट रूप से लागू होती हैं। उन टिप्पणियों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने एससीसी के अनुच्छेद 28 में ए. सुबैर मामले में यह स्पष्ट हो गया कि अभियोजन पक्ष को अन्य किसी भी आपराधिक मामले की तरह ही आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति का युक्तियुक्त प्रमाण न मिल जाए, जो रिश्वतखोरी के मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कानून के उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों को देखते हुए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना कठिन लगता है।

23. वर्तमान प्रकरण में, अपने बचाव में, अपीलकर्ता ने प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-  
1) की परीक्षण कराया और बचाव में कहा कि परिवादी अपने खेत में लगे ट्यूबवेल का दुरुपयोग करके पानी बेच रहा था, इसलिए ट्यूबवेल की बिजली काट दी गई थी और परिवादी को बताया गया था कि बकाया राशि के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करने





पर बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा। इसी संबंध में, परिवादी ने उसे 2,000 रुपये यह कहते हुए दिए कि वह स्टेशन से बाहर जा रहा है, इसलिए उसे 2,000 रुपये की रसीद बाद में मिल जाएगी, लेकिन ट्यूबवेल की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

24. एस.एस.पांडे (अ.सा.-1) ने पैराग्राफ 5 में प्रति-परीक्षण में गवाही दी कि अपीलकर्ता ने जांच दल को बताया था कि परिवादी की बिजली काट दी गई है, इसलिए परिवादी ने उसे बिजली आपूर्ति बहाल करने और बकाया राशि के भुगतान के रूप में 2,000 रुपये दिए थे। अपीलकर्ता ने आगे बताया कि कार्यालय बंद था, इसलिए वह 2,000 रुपये के भुगतान की रसीद देने की स्थिति में नहीं था। उसने आगे बयान दिया कि परिवादी ने यह नहीं बताया था कि अपीलकर्ता 2,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था, बल्कि उसने बताया था कि अपीलकर्ता बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 2,000 रुपये मांग रहा था। उसने आगे बयान दिया कि टेप रिकॉर्डर चलाया गया था, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही थी।

25. रामानंद सोनी (अ.सा.-2) ने बयान दिया कि अपीलकर्ता के आदेश पर परिवादी की बिजली काट दी गई थी। उसने आगे बयान दिया कि परिवादी मोटर पंप से निकाले गए पानी का दुरुपयोग कर रहा था। उसने आगे बयान दिया कि अपीलकर्ता ने उसे बताया था कि परिवादी के पिता महेश देवांगन द्वारा 2,000 रुपये का भुगतान करने पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने आगे बयान दिया कि अपीलकर्ता ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि जब परिवादी बिजली बिल के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करेगा, तभी बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।

26. पी.एन.सिंह (अ.सा.-3) ने बयान दिया कि उपभोक्ता ने कार्यालय में 2,012 रुपये का भुगतान किया था, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। उन्होंने



आगे बयान दिया कि यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल कार्यालय समय के बाद वसूले जाते हैं और उनकी रसीदें अगले दिन जारी की जाती हैं।

27. पी.एस. कुमार (अ.सा.-9) ने गवाही दी कि 27-4-2002 से 6-6-2003 तक वे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, रायपुर में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात थे। उन्होंने आगे गवाही दी कि प्रदर्श पृष्ठ-15, प्रदर्श पृष्ठ-16 और प्रदर्श पृष्ठ-17 से संबंधित जानकारी उनके कार्यालय से लोकायुक्त को दी गई थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि प्रदर्श पृष्ठ-18 की रिपोर्ट एस.एस. मौर्य द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने आगे गवाही दी कि यह सच है कि परिवादी की बिजली आपूर्ति काटने के बाद, परिवादी द्वारा 2,012 रुपये जमा किए गए थे, जिसका विवरण प्रदर्श पृष्ठ-15 में है। यह सच है कि पिछले दो वर्षों में, परिवादी पर कृषि मोटर पंप का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

28. प्रकाश अग्रवाल (व.सा.-1) ने गवाही दी कि 15-1-2002 को वे और अपीलकर्ता उनके कार्यालय में बैठे थे। उन्होंने आगे बयान दिया कि जब वे चाय पी रहे थे, तब परिवादी रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) वहाँ आए। उन्हें भी चाय पिलाई गई। परिवादी ने अपीलकर्ता से 2,000 रुपये की राशि रखने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध किया और यह भी बताया कि चूंकि उन्हें स्टेशन से बाहर जाना है, इसलिए वे भुगतान की रसीद बाद में ले लेंगे। अपीलकर्ता ने परिवादी से राशि कार्यालय में जमा करने और उसकी रसीद लेने को कहा। परिवादी के अनुरोध पर, अपीलकर्ता ने परिवादी से पैसे ले लिए और परिवादी के बार-बार अनुरोध करने पर, अपीलकर्ता ने परिवादी के लिए बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए फोन किया।

29. रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) ने पैराग्राफ 16 में प्रति-परीक्षण के दौरान बयान दिया कि वे प्रकाश राइस मिल के मालिक प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-1) को



बचपन से जानते थे। उनके और प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-1) के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। जब उनके और अपीलकर्ता के बीच बातचीत हुई, उस समय प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-1) वहां मौजूद थे।

30. अमलदास लकड़ा (अ.सा.-5) और एस.एस. पांडे (अ.सा.-1) के साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने परिवादी और अपीलकर्ता के बीच हुई बातचीत नहीं सुनी और न ही उन्होंने परिवादी को अपीलकर्ता को पैसे देते हुए देखा। किसी जालसाजी के मामले में, कम से कम कुछ पंच गवाहों को बातचीत सुननी चाहिए या कुछ ऐसा देखना चाहिए जिसके बारे में वे गवाही दे सकें। इस तरह के मामले में कथित घटना और रिश्त लेने के समय वास्तव में क्या हुआ था, इसकी पुष्टि करना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में, उपरोक्त तथ्यों का घोर अभाव है।

31. परिवादी रामावतार देवांगन (अ.सा.-4) के अनुसार, उन्होंने प्रकाश अग्रवाल (अ.सा.-1) की उपस्थिति में अपीलकर्ता को 2,000 रुपये दिए थे। मेरा मानना है कि किसी लोक सेवक के लिए किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अवैध रिश्त की मांग करना और उसे स्वीकार करना संभव नहीं है।

32. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी आरोपी की दोषसिद्धि अनुमान के आधार पर नहीं की जा सकती। आरोपी के विरुद्ध अपराध को प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए। यदि घटनाक्रम की प्रत्येक कड़ी आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती है, तो अभियोजन पक्ष को इस संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, जो युक्तियुक्त साक्ष्य द्वारा समर्थित एक पूर्ण घटनाक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।





33. अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत अनुमान के संबंध में, यह सर्वविदित है कि धारा 20 के तहत सुस्थापित अनुमान अचूक नहीं है। अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने विरुद्ध उद्धृत गवाहों से प्रति-परीक्षण करके या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है। यदि आरोपी इस अनुमान को गलत साबित करने में विफल रहता है, तो यह अनुमान मान्य रहेगा और तब न्यायालय यह मान सकता है कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपी ने रिश्त के रूप में राशि स्वीकार की थी। यह भी सर्वविदित है कि अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत जिस आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध अनुमान लगाया गया है, उस पर साक्ष्य का भार अभियोजन पक्ष पर युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को सिद्ध करने के भार के समान नहीं है। यदि आरोपी व्यक्ति अपने मामले के पक्ष में प्रबल संभावना सिद्ध करने में सफल होता है तो यह पर्याप्त है। आरोपी व्यक्ति के लिए अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, अन्यथा उसे दोषी ठहराया जाएगा। अभियुक्त पर साक्ष्य का भार होता है कि वह संभाव्यता की प्रबलता से अपना प्रकरण सिद्ध करे। जैसे ही वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, भार अभियोजन पक्ष पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे अपना मूल भार निभाना होता है, जो कभी नहीं बदलता, अर्थात् पूरे मामले में अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना।

34. वर्तमान प्रकरण में, यह स्पष्ट है कि परिवादी के अनुरोध पर, अपीलकर्ता ने बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 2,000 रुपये की राशि स्वीकार की थी। अपीलकर्ता ने परिवादी को कार्यालय में राशि जमा करने और उसकी रसीद लेने के लिए कहा था। परिवादी के अनुरोध पर, अपीलकर्ता ने परिवादी से पैसे ले लिए और परिवादी के बार-बार अनुरोध करने पर, अपीलकर्ता ने परिवादी के लिए बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए फोन किया।



35. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने धन स्वीकार कर लिया था और उसे अपनी जेब में रख लिया था, इसलिए जब अपीलकर्ता की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। एस.एस. पांडे (अ.सा.-1) ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उन्होंने परिवादी और अपीलकर्ता के बीच हुई बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं सुना था, इसलिए केवल अपीलकर्ता से धन की बरामदगी से ही उसके विरुद्ध अभियोजन के आरोप सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि रिश्वत के भुगतान या यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से धन या अवैध रिश्वत स्वीकार की थी।

36. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) के साथ सह पठित धारा 13(2) के तहत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और सजा अपास्त की जाती है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वर्तमान में, वह जमानत पर है। उनकी बंद-पत्र-निरस्त की जाती है और प्रतिभू उन्मोहित किया जाता है।

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**